



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 1985/अश्विन 23, 1907

No. 503]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 1985/ASVINA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(प्राधन कार्य विभाग)

अधिलेखना

नई दिल्ली 15 अक्टूबर, 1985

बीमा

का०आ० 769(ख)---केन्द्रीय सरकार, माध्याग्न बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थापन और पुनरीक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 17-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्याग्न बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थापन और पुनरीक्षण) अधिनियम 1974 में और मंजूर कर के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् ---

1 (1) इस स्कीम का मक्षिप्त नाम माध्याग्न बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थापन और पुनरीक्षण) अधिनियम 1985 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1983 का प्रवृत्त हुई माना जाएगा।

(3) यह उन सब कर्मचारियों पर लागू होगी जो ---

(1) इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख को निगम अथवा कंपनी के पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, और

(11) जो इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् निगम अथवा कंपनी द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए जाने हैं,

किन्तु यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी ---

(क) जो 1 अप्रैल, 1983 का या उसके पश्चात् वर्ष 1 अधिकारी के रूप में प्रोन्नत हो गए हैं या विकास कर्मचारियों के रूप में मपरिचालित हो गए हैं,

(ख) जो नियोजन की विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नियोजित किए गए हैं,

(ग) जो अस्थायिक रूप से नियोजित हैं, या

(घ) जिसका इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ने पूर्व स्थापित स्वीकार कर लिया गया था या जिसकी स्थापना समाप्त कर दी गई थी।

2 माध्याग्न बीमा (पर्यवेक्षकीय लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थापन और पुनरीक्षण) अधिनियम 1974 (जिसे इसमें इसका पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में ---

(1) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तर्गत किया जाएगा, अर्थात् ---

(ख) 'निगम' में अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित भारतीय माध्याग्न बीमा निगम अधिनियम है।

(ii) खंड (चक और बख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात् —

“(चक) ‘‘पुनर्गठित निबंधना’’ में चांश अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्गठित वेतनमान प्राप्त करने और है ,

(बख) पुनर्गठित वेतनमानों में चांश अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्गठित वेतनमान अभिप्रेत है ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 1 के उपपैरा (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखे जाएंगे अर्थात् —

(4) माधारण बीमा (परिवेशकीय निषिकीय और अर्धीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अवधि की सुव्यवस्थाकरण और पुनर्गठन) मणोधन स्कीम 1985 (जिसे इसमें इसका अंगे मणोधन स्कीम कहा गया है) के प्रावधानों के तारीख से, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन और भत्ते ‘‘पुनर्गठित निबंधनों के अनुसार द्वारा और उस तारीख के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक कर्मचारी का निम्नका मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाता है 1 अप्रैल 1983 या उसकी नियुक्ति की तारीख जा भी बाद में है के प्रावधानों के तारीख से, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन और भत्ते ‘‘पुनर्गठित निबंधनों के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाता है ।

परन्तु यह कि —

(1) उस कर्मचारी का जो 1 अप्रैल 1983 के पश्चात् सेवा में रहने का दावा करने वाला है, उसका वेतन और भत्ते ‘‘पुनर्गठित निबंधनों के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाता है ।

(11) उस कर्मचारी के मामले में जिसकी 1 अप्रैल 1983 के पश्चात् सेवा में रहने का दावा करने वाला है, उसका वेतन और भत्ते ‘‘पुनर्गठित निबंधनों के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाता है ।

परन्तु यह भी कि उस कर्मचारी के मामले में जो 1 अप्रैल 1983 का या उसके पश्चात् परिवेशकीय निषिकीय और अर्धीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों में प्रविष्ट किया गया है अथवा विकास कर्मचारी के रूप में संप्रविष्टित किया गया है या अधिकारी के रूप में उसकी प्रवृत्ति या विकास कर्मचारी के रूप में संप्रविष्टित की तारीख तक की प्रवृत्ति अन्तर की धनराशि (उपदान के अन्तर की धनराशि का छोड़कर) का भगवान पुनर्गठित निबंधनों में उसके मूल वेतन के वैधानिक नियतन के आधार पर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—उप पैरा (5) के प्रयोजन के लिए ‘‘अन्य भत्ते’’ पर में मकान विराण्ड भत्ता नगर प्रतिकरात्मक भत्ता कार्यात्मक भत्ता गर्वनीय ग्यान भत्ता तथा तर्कीकी अर्धीनस्थ के लिए ऐसा भत्ता अभिप्रेत है जो कर्मचारी को अनुज्ञेय है ।

4. उक्त स्कीम के तारीख (4) के पश्चात् पुनर्गठित पैरा रखे जाएंगे अर्थात् —

परन्तु यह कि जहां ऐसे कर्मचारी को 1 अप्रैल 1983 का वापिस वेतनवृद्धि दया जाता है उसमें वेतनवृद्धि मूल वेतन के ऐसे नियतन के आक पश्चात् पुनर्गठित वेतनमान में दी जाएगी ।

(1) सेवान्वय प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन 31 मार्च, 1983 का या वह 1 अप्रैल 1983 से मुसगत पुनर्गठित वेतनमान के तत्पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाएगा ;

परन्तु यह कि जहां ऐसे कर्मचारी को 1 अप्रैल 1983 का वापिस वेतनवृद्धि दया जाता है उसमें वेतनवृद्धि मूल वेतन के ऐसे नियतन के आक पश्चात् पुनर्गठित वेतनमान में दी जाएगी ।

परन्तु यह और कि जहां ऐसे कर्मचारी का मूल वेतनमान मुसगत वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाता है या ऐसे कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी ।

(2) 1 अप्रैल 1983 का या उसके पश्चात् किन्तु राजपत्र में स्कीम मणोधन प्राणान में पूर्ण नियुक्ति किए गए प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन उसकी नियुक्ति की तारीख से मुसगत पुनर्गठित वेतनमान के तत्पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6 के उपबन्ध के अनुसार पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाएगा ;

परन्तु यह कि मूल वेतन के नियतन पर फायदे (अर्थात् ‘‘पुनर्गठित निबंधनों’’ के अर्धीन मूल वेतन और महंगाई भत्ते के जोड़ की ‘‘विद्यमान निबंधनों’’ के अर्धीन मूल वेतन वैधानिक वेतन यदि कोई हो, के जोड़ की अपेक्षा बृद्धि उक्त तारीख के तत्पश्चात् (1) में की तत्पश्चात् प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के प्रत्येक कर्मचारी के मामले में उसमें उपावृद्धि मांगनी के तत्पश्चात् (2) में विनिर्दिष्ट स्कीम में कम नहीं होगा —

सारणी

कर्मचारी प्रवर्ग स्थानगत प्रतिमास फायदे

(1)	(2)
अर्धीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान	35 रुपये
रिक्त निषिक	40 रुपये
महंगाई वेतनमान में सभी कर्मचारी	50 रुपये
वर्गिक महंगाई/आवृत्तिक/अर्धीनस्थ	60 रुपये

परन्तु यह भी कि यदि मुसगत पुनर्गठित वेतनमान के तत्पश्चात् प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन के नियतन के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को पूर्वोक्त तारीखों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम फायदे नहीं होते हैं या उस कर्मचारी का मूल वेतन मुसगत पुनर्गठित वेतनमान के उसमें उच्चतर एक या अधिक पक्षों पर उस प्रकार नियत किया जाएगा जिसमें कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे पूर्वोक्त तारीखों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम फायदे मिले ।

परन्तु यह भी कि जहां मुसगत पुनर्गठित वेतनमान के अधिकतम पर मूल वेतन के नियतन में पूर्वोक्त तारीखों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम फायदे कर्मचारी को नहीं देता या उसे उस कर्मचारी के अर्धीनस्थ ‘‘समायोजन भत्ता’’ दिया जाएगा जिस भत्ते का मणोधन स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का या उसके पश्चात् दया मूल वेतन अथवा महंगाई भत्ते में प्रविष्टि में देना वाली किसी व्यक्ति में समायोजन कर दिया जाएगा ।

(3) (क) उपपैरा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी कर्मचारी हम बात का बताकर सकता है कि उसका मूल वेतन मणोधन स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में पुनर्गठित वेतनमानों में नियत किया जाए उस दशा में वह नियम या कर्तव्य को इस तथ्य के सूचना मणोधन स्कीम के तत्पश्चात् प्रकाशन की तारीख में मीमांसा के भीतर या कर्तव्य के प्रवृद्धि-निर्देशक अथवा अध्यक्ष-मह-अध्यक्ष निदेशक, द्वारा अनुज्ञेय किसे बड़ाई गई अवधि तक निश्चित रूप में देना ।

(ख) जहाँ कर्मचारी अपना मूल वेतन मणोधन स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख से नियत करवाने का अधिकार देता है तो "पुनर्गठित निबंधनों" में उसके वेतन का नियतन, यथा पूर्ववर्ति रीति में जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ति न्यूनतम फायदे हैं किन्तु मणोधन स्कीम में ऐसे प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व तारीख को "विद्यमान निबंधनों" के अर्थात् उसकी कुल परिणतिधियाँ (अर्थात् मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ता और वैयक्तिक भत्ता) के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु "विद्यमान निबंधनों" के अर्थात् कर्मचारी का परिणतिधियों की पुनर्गठना सैद्धांतिक आधार पर भा तहों की जाएगी और मणोधन स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पहले की अवधि के लिए उसे कोई वकाया राशि संदेय नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि जहाँ मणोधन स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख में ठीक पूर्ववर्ती तारीख की पर्यवेक्षणीय और लिपिकीय गवर्णों के ऐसे किसी कर्मचारी का "विद्यमान निबंधनों" के अनुसार कुल परिणतिधियाँ (अर्थात् मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ता और वैयक्तिक भत्ता) और पूर्ववर्ति न्यूनतम फायदे का योग "पुनर्गठित निबंधनों" के अधीन उसके परिणतिधियाँ (अर्थात् मूल वेतन, महंगाई भत्ता और समायोजन भत्ता, यदि कोई हो) में अधिक हो, तो ऐसे कर्मचारी की कुल परिणतिधियों का, "पुनर्गठित निबंधनों" के अधीन उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा समायोजन भत्ता, यदि कोई हो, के कुल योग तथा 35-00 रुपए के अन्तर को राशि तक वैयक्तिक भत्ता देकर और शेष को यदि कोई हो, संरक्षण भत्ता देकर संरक्षित किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि वैयक्तिक भत्ता मणोधन स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख की या उसके पश्चात् कर्मचारी का देय मूल वेतन या महंगाई भत्ता में अतिरिक्त से होने वाले वांछित वृद्धि में समायोजित कर दिया जाएगा। संरक्षण भत्ता कर्मचारी का अधिकारी की श्रेणी में प्रोन्नति होने का तारीख तक अग्रमाविष्ट रहेगा। कर्मचारी का प्रोन्नति अधिकारी की श्रेणी में हो जाने पर सर्वप्रथम वैयक्तिक भत्ता, यदि कोई हो, ऐसी प्रोन्नति पर कुल परिणतिधियों में, यथासंभव सीमा तक, समाविष्ट किया जाएगा और जब पूर्ण वैयक्तिक भत्ता समाविष्ट हो जाता है तो संरक्षण भत्ता, अधिकारी की श्रेणी में प्रोन्नति पर कर्मचारी का कुल परिणतिधियों में, यथा संभव सीमा तक समाविष्ट किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि जहाँ अधिकारी की श्रेणी में प्रोन्नति हो जाने पर भी यथास्थिति वैयक्तिक भत्ता और/अथवा संरक्षण भत्ता पूर्णतया समाविष्ट नहीं होता है, तो अग्रमाविष्ट अतिरिक्त प्रोन्नति के पश्चात् भी उप प्रकार जारी रहेगा।

परन्तु यह भी कि यथास्थिति, ऐसा वैयक्तिक भत्ता और/अथवा संरक्षण भत्ता जो ऐसी प्रोन्नति के पश्चात् जारी रहेगा, उसे परिणतिधियों में अतिरिक्त से होने वाले वृद्धियों में उस प्रकार समाविष्ट किया जाएगा जैसा निगम के अध्यक्ष द्वारा चिन्तित किया जाय।

परन्तु यह भी कि किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन सुसंगत पुनर्गठित वेतनमान के अधिकतम से अधिक मूल वेतन पर नियत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि जहाँ सुसंगत पुनर्गठित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने पर परिणामस्वरूप, कर्मचारियों का मूल वेतन "विद्यमान निबंधनों" के अधीन सुसंगत वेतनमान के निम्नतर या अथवा अधिक प्रक्रमों र संबंधित पुनर्गठित वेतनमान के समान प्रक्रम पर हो नियत जाता है तो निगम का अध्यक्ष उन कर्मचारियों की जो "विद्यमान निबंधनों" के अधीन वेतनमान में उच्च प्रक्रम पर है, उनके सामान्य वृद्धि वेतन की तारीख से पहले अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर, उपयुक्त हित प्रदान कर सकता है।

5. उक्त स्कीम के पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा अर्थात् :-

"7. वेतन वृद्धियाँ—(1) मणोधन स्कीम के गजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से किसी कर्मचारी को उसे लागू ग्रेड में वेतन

वृद्धियाँ प्रत्येक वर्ष उस मास की पहली तारीख की जिसमें पिछली वेतन वृद्धि प्राप्त की थी अथवा उस मास की पहली तारीख की जिसमें वह निरन्तर सेवा के बारह मास पूरे करता है, देव होगी।

स्पष्टीकरण— इस उप पैरा के प्रयोजनार्थ "बारह मास की निरन्तर सेवा" से, असाधारण छुट्टी की अवधियों की छोड़कर इग्रेडी की बारह मास के बराबर अवधि अभिप्रेत है।

(2) उस कर्मचारी (अधीनस्थ से भिन्न) को बाबत जिसका मूल वेतन पैरा 6 के अधीन 1 अप्रैल, 1983 को अथवा मणोधन स्कीम के गजपक्ष में प्रकाशन की तारीख की पुनर्गठित वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाता है और उस कर्मचारी को बाबत जो अपने सेवाकाल में उसके पश्चात् किसी भी समय पुनर्गठित वेतनमान में अधिकतम पर पहुँचने है, यथापरिस्थिति प्रवृद्धि निदेशक अथवा अध्यक्ष मह-प्रबंध निदेशक कर्मचारी के कार्य का रिकार्ड सत्यापन प्राप्त पर, महायका, चालक अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान में ऐसे कर्मचारी को संबंधित पुनर्गठित वेतनमान में उसके अधिकतम पर पहुँचने की तारीख के पश्चात् उसके द्वारा की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए उस वेतनमान में प्राप्त की गई यतिम वेतन वृद्धि का दर पर, एक वेतन वृद्धि देने पर विचार कर सकेगा और ऐसी तीन से अधिक वेतनवृद्धियाँ नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह कि ज्येष्ठ महायका, आशुलिपिकों और अभिलेख लिपिकों के वेतनमानों में ऐसे कर्मचारी को संबंधित पुनर्गठित वेतनमान में अधिकतम पर पहुँचने की तारीख का बाद कर्मचारी द्वारा की गई प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा के लिए संबंधित पुनर्गठित वेतनमान में ऐसी एक वेतन वृद्धि दी जा सकेगी और इस उपपैरा के अधीन ऐसी दो वेतन वृद्धियों से अधिक संभव नहीं की जाएगी।

6. उक्त स्कीम के पैरा 8 में उप पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अन्तर्भावित किया जाएगा अर्थात् :-

(4) उप पैरा उपपैरा (1) और (2) में नियत अधिकतम साप्ताहिक कार्य समय के अधीन रहते हुए समय-समय पर निगम का बाई एक सप्ताह का कार्य कर सकेगा।

7. उक्त स्कीम के पैरा 10 में, ---

(3) उप पैरा (3) में विद्यमान खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् ---

(ग) जहाँ किसी कर्मचारी के खाने में अजित छुट्टी जमा है किन्तु उसमें उसका उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके खाने में सेवा निवृत्ति की तारीख की जमा अजित छुट्टी की अवधि को बाबत निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि का संदेय किया जा सकेगा अर्थात् :-

- (i) 180 दिन यदि कर्मचारी की सामान्य सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, और
- (ii) 120 दिन, यदि कर्मचारी की सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है,

परन्तु यह कि उसकी मृत्यु की तारीख की उसके खाने में जमा अजित छुट्टी भुनाने को अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

परन्तु यह और कि यह खंड उस कर्मचारी का लागू नहीं होगा जिसे कि साधारण बीमा (आवरण, अनुश्रामन और अर्पण) नियम, 1975 के अनुसार सेवा में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया है, हटाया गया है या पदच्युत किया गया।

टिप्पण 1—“अजित छुट्टी को भुतान के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी को देय रकम का अवधारण करने के लिए—

- (क) सेवानिवृत्ति की दशा में, छुट्टी वेतन उसकी ऐसी छुट्टियों के जो उसके नाम जमा है, के लिए वेतन के बराबर होगा जो वेतन की उम्र दर से परिकलित किया जाएगा जिस दर उसने अपनी सेवानिवृत्ति की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को वेतन लिया था किन्तु इसके अंतर्गत नगर प्रतिकाशत्मक भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता और कार्यात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है।
- (ख) किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, उसकी सकल कृत परि-
नधियों को (मूल वेतन धन सभी भत्ते, जिसके अंतर्गत कार्यात्मक भत्ता और स्थानापन्न भत्ता सम्मिलित नहीं है) जो मृत्यु की तारीख को है, हिमाव में लिया जाएगा।”

टिप्पण 2—किसी कर्मचारी को, अजित छुट्टी को भुतान के परिणामस्वरूप देय कोई रकम, उसकी मृत्यु की तारीख को उसके खाते में शेष है तो उसका सदाय उस व्यक्ति को, जिसे संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि सदेय है, किया जाएगा।

टिप्पण 3—छुट्टी वेतन के बराबर नकदी का भुतान एक ही बार में परिनिर्धारण के रूप में, एक मूल रकम में सदाय किया जाएगा।

टिप्पण 4—छुट्टी वेतन के बराबर नकदी मंजूर करने के लिए प्राधिकारी, संबंधित कर्मचारी को छुट्टी मंजूर करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी होगा।

(2) उप-पैरा (5) में विद्यमान परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित परन्तु रखा जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु यह कि यदि कोई कर्मचारी आठ मुख्य रोगों केल्सर, कुष्ठ, क्षयरोग, अमवात, मस्तिष्क ट्यूमर, हृदय के रोगों, वृक्क रोगों तथा मानसिक रोगों में से किसी रोग में पीड़ित हो तो उसे यदि उसके खाने में कोई रोग छुट्टी अनुज्ञेय नहीं तो उसे छह मास में अनधिक अवधि के लिए अर्ध वेतन पर विशेष रोग छुट्टी दी जा सकेगी।”

8. उक्त स्कीम के पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

“13 उपदान—(1) किसी कर्मचारी का उपदान सदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबन्धों के अनुसार सदाय किया जाएगा

परन्तु यह कि “मणोधन स्कीम” के अधीन सदेय उपदान इस शर्त के अधीन रहने हुए किसी भी दशा में 20 मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगा कि—

- (i) जहां किसी कर्मचारी द्वारा अन्तिम प्राप्त मजदूरी 1600 रुपये से अधिक है वहां उसे, उपदान की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, 1600 रुपये समझा जाएगा, और
- (ii) जिस दर से उपदान का सदाय किया जाएगा, वह निम्नलिखित रूप में बढ़ी हुई होगी—

मेवा के सम्पूर्ण वर्षों की संख्या	मेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए मास की मजदूरी संख्या में उपदान की दर
12	0.6
13	0.7
14	0.8
15 या अधिक	1.0

स्पष्टीकरण : इस पैरा में, “मजदूरी” से बड़ी अभिप्रेत होगा जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 2 के खंड (घ) में है।

(2) उप पैरा (1) में निर्मा बात के होते हुए भी, किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसने 15 वर्ष में अप्रुप निरन्तर सेवा की है, उस उपदान का सदाय किया जाएगा जो नीचे के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अनुसार परिकलित की गई दोनों रकमों में से अधिक होगा—

(1) उप पैरा (i) के अनुसार परिकलित उपदान;

(ii) प्रथम पंद्रह वर्षों का बाबत निरन्तर सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के सेवान्तर मूल वेतन को दर से और आगे का निरन्तर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे महीने के सेवान्तर मूल वेतन की दर से उपदान इस शर्त के अधीन रहने हुए कि इस प्रकार अनुज्ञेय कुल उपदान अधिकतम 20 मास के सेवान्तर मूल वेतन या 36,000 रुपये से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा।

9. उक्त स्कीम के पैरा 19 में, उप पैरा (2) में “यंत्रिकरण” शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में ऐसे माईक्रोप्रोसेसरों का, या प्रबंध सूचना के लिए और प्रभावी नियंत्रण के लिए डाटा का समय पर उत्पत्ति और उमक शोध संसाधन के लिए आवश्यक हो, प्रयोग भी है।”

10. उक्त स्कीम के पैरा 20 का लोप किया जाएगा।

11. उक्त स्कीम के पैरा 24 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्—

“21 अन्य प्रमुविधायक—कोई भी कर्मचारी किसी ऐसी प्रमुविधा का हकदार नहीं होगा जो “इस स्कीम” या किसी ऐसी स्कीम जो निगम या कम्पनी द्वारा बनाई जाए, से उद्भूत न हो।”

12. उक्त स्कीम की नींवरी अनुसूची में,

- (i) खंड (क) में “15” अंक के स्थान पर “7” अंक रखा जाएगा;
- (ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्—

“निगम या कम्पनी, कर्मचारी को, प्रत्येक और से 1208 किलोमीटर तक की यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी।”

(iii) खंड (ड) में,

- (क) “1000” अंकों के स्थान पर “1208” अंक रखे जाएंगे;
- (ख) “उपपैरा” शब्द के स्थान पर “खंड” शब्द रखा जाएगा;
- (iv) खंड (च) में “15 दिन से अधिक” अंकों और शब्दों के स्थान पर “7 दिन से अमृत” अंक और शब्द रखे जाएंगे

13. उक्त स्कीम में, नीचे अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखा जाएगी, अर्थात्—

“नीचे अनुसूची

(पैरा 3(क) और (च) देखें)

I. पुनर्गठित वेतनमान (मूल वेतन)

(क) पर्यवेक्षण और निपिकीय कर्मचारियों—

(1) अधीक्षक (रन ऑफ काउन्टर)*

1060-75-2035-80-2135 रुपये

(2) ज्येष्ठ सहायक

715-60-1135-75-2035 रुपये

(3) आभिलषिक :

715-60-1135-75-2015 रुपये

*निगम या कम्पनी द्वारा अर्थात् के पदों पर कोई नहीं नियुक्ति की जाएगी।

- (4) महायक, टाईपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलिग्राफ ऑपरेटर, स्वागतकर्ता, पत्र-कार्ड ऑपरेटर, यूनिट रिकार्ड भर्तान ऑपरेटर, काम्पटिस्ट और अन्य समतुल्य पद.
520-30-670-15-850-60-1210-75-1660 रुपये

(5) अभिलेख लिपिक

490-20-730-35-905-45-1130 रुपये

ख. अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द :

(1) ड्राईवर.

190-20-750-25-300-30-980 रुपये

(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द

430-10-450-20-790 रुपये

II. कार्यात्मक भत्ता

अन्तर्निर्धारित और मुख्य कार्य के रूप में निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य में योग्यकर्मचारियों को नीचे उपदिष्ट के अनुसार कार्यात्मक भत्ते का संदाय किया जाएगा :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (1) लिफ्टमैन, भर्तान ऑपरेटर, प्रधान चपरासी, इमादार या दफतरी के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्म-चारिवृन्द | 35 रुपये प्रतिमास |
| (2) बैंक में रोकड़ लाने या बहा ले जाने का कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द, जहाँ किसी क्लेडर मास के दौरान लागू हो जाय गण रोकड़ की रकम सामान्यतः 25,000 रुपये या उससे अधिक है | 25 रुपये प्रतिमास |
| (3) किसी ऐसी कार्यालय में रोकड़ सभालन वाला रोकड़िया जहाँ किसी क्लेडर मास के दौरान तदर्थ सव्यवहार को कुल रकम सामान्यतः 25,000 रुपये या उससे अधिक है | 75 रुपये प्रतिमास |
| (4) टेलिग्राफ ऑपरेटर, पत्र कार्ड ऑपरेटर और यूनिट रिकार्ड भर्तान ऑपरेटर | 10 रुपये प्रतिमास |
| (5) काम्पटिस्ट | 40 रुपये प्रतिमास |
| (6) निगम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, महायक महाप्रबंधक और समतुल्य अधिकारियों के आशुलिपिक | 50 रुपये प्रतिमास |
| (7) लेखापरीक्षा महायक | 200 रुपये प्रतिमास |

टिप्पण 1: कार्यात्मक भत्ता पाने के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा मंडला और गाम, कार्य-भार तथा प्रशासनिक अवेदाओं पर निर्भर करने हुए अध्यक्ष महा-प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

टिप्पण 2: कोई भी कर्मचारी किसी एक समय पर केवल एक कार्यात्मक भत्ता लेगा।

टिप्पण 3: छुट्टी पर जाने वाले किसी कर्मचारी को, असाधारण छुट्टी की अवधियों से भिन्न उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कार्यात्मक भत्ता दिया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी पद पर कार्य आरंभ करता है।

टिप्पण 4: कोई भी कर्मचारी, उस पद से संलग्न कार्यात्मक भत्ता पाने के लिए, अधिकार के रूप में, किसी विशिष्ट भाग का कार्य उसे आवंटित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

टिप्पण 5: कोई भी कर्मचारी कार्यात्मक भत्ता वाले किसी पद पर कार्य करने को इस्कार नहीं करेगा या यह बात नहीं लगाएगा कि पदधारी की अनुपस्थिति या अस्थायी रूप से कार्य बंद होने के कारण, कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य उसे सौंपा गया है इसलिए उसे ऐसा भत्ता दिया जाए।

III. महंगाई भत्ता

(i) कर्मचारियों का लागू महंगाई भत्ते का सापेक्ष निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :—

सूचक औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत औद्योगिक मूल्य सूचकांक।

आधार वर्ष : 1960-100

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण :—महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 प्वाइंट की वृद्धि या गिरावट के लिए निम्नाधार पर किया जाएगा।

महंगाई भत्ते का दर : 332 प्वाइंटों में ऊपर, निम्नाधार औसत के प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों में परिकलित किया जाएगा :—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (i) 790 रुपये या उससे कम मूल वेतन | मूल वेतन का 1/2 प्रतिशत |
| (ii) 790 रुपये से अधिक मूल वेतन | मूल वेतन का 1 प्रतिशत, किन्तु न्यूनतम 9.48 रुपये और अधिकतम 15.80 रुपये। |

(2) अखिल भारतीय औद्योगिक मूल्य सूचकांक के निम्नाधार औसत (जिसे उससे इनके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 332 प्वाइंटों में ऊपर होने पर 332-336-340-344 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संवेय महंगाई भत्ते का उध्वंगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है तब उसके सदर्थ में पिछली पूर्ववर्ती निम्नाधार के लिए महंगाई भत्ता दिया गया है, तो संवेय महंगाई भत्ते का उध्वंगामी पुनरीक्षण होगा। उध्वंगामी पुनरीक्षण होने पर, संवेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है, और यदि ऐसा चालू औसत अंक, अनुक्रम में कोई अंक नहीं है, तो संवेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है। इस प्रयोजन के लिए निम्नाधार से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी। भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में प्रकाशित अन्तिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट निम्नाधार के लिए, चालू औसत सूचकांक में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस निम्नाधार की समाप्ति के बाद केवल दूसरे उत्तरवर्ती मास में प्रभावी होगा।

(4) संवेय के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1983 को संवेय महंगाई भत्ता वह रकम होगा जो 332 से ऊपर 160 प्वाइंटों पर इससे विनिर्दिष्ट दर के अनुसार अवधारित है और उसके पश्चात् उसी निम्नाधार पुनरीक्षण उस मास की पहली तारीख का शीघ्र समझे जाएंगे जिसमें निम्नाधार औसत सूचकांक उपलब्ध थे। तदनुसार, अप्रैल 1983 के लिए संवेय महंगाई भत्ता वह होगा जो नीचे दी गई मारणी में प्रथम प्रविष्टि में उपदिष्ट है और उसके पश्चात् कि ऐसा भत्ता मारणी में आनुपूर्विक प्रविष्टियों के अनुसार पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा।

मासों के लिए सदैव महंगाई भत्ता	चार चार्टर्ड के गुणों में से सूचक निमाहाओमन सूचक	332 के अन्तर्गत चार्टर्ड के सूचक जिनके लिए महंगाई भत्ता सदैव है	दर 790 रु.	790 रु.	मे उपर का मूल वेतन
			प्रति-शत	प्रति-शत	
अप्रैल, 1983	492	160	18		40
मई, 1983 से जुलाई, 1983	496	161	19	2	11
अगस्त, 1983 से अक्टूबर, 1983	520	188	56	4	47
नवम्बर, 1983 से जनवरी, 1984	518	218	61	8	51
फरवरी, 1984 से अप्रैल, 1984	556	226	67	2	56
मई, 1984 से जुलाई, 1984	560	228	68	4	57
अगस्त, 1984 से अक्टूबर, 1984	561	252	69	6	58
नवम्बर, 1984 से जनवरी, 1985	584	252	75	6	63
फरवरी, 1985 से अप्रैल, 1985	588	256	76	8	64
मई, 1985 से जुलाई, 1985	584	252	75	6	63
अगस्त, 1985 से अक्टूबर, 1985	600	268	80	4	67

प्रथम शीर्ष के अधीन प्रविष्टि (i) की उप-प्रविष्टि (ii) में उपदर्शित न्यूनतम और अधिकतम रकमों के अधीन रहते हुए।

IV. वेतन का अधिकतम सीमा—

कोई भी कर्मचारी, जो—

- यथास्थिति, निगम या कम्पनी के पर्यवेक्षी या लिपिकीय स्टाफ में कार्य कर रहा हो, किसी भी समय, मूल वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ते और वैयक्तिक भत्ते के रूप में कुल 3500 रु प्रतिमास से अधिक रकम प्राप्त नहीं करेगा,
- यथास्थिति, निगम या कम्पनी के अधीनस्थ स्टाफ में कार्य कर रहा हो, किसी भी समय, मूल वेतन, विशेष वेतन, यदि कोई हो, महंगाई भत्ते और वैयक्तिक भत्ते के रूप में कुल 2100 रुपये प्रतिमास से अधिक रकम प्राप्त नहीं करेगा।

V. तर्जुमों अर्हताओं के लिए भत्ता—

किसी पद किए ग कर्मचारी को, जो नीचे उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हता होता है या जिसमें अर्हता किया है, परीक्षा के परिणाम के

प्रकाशन की तारीख से, नीचे उल्लिखित तर्जुमों की अर्हताओं के लिए भत्ता दिया जाएगा—

परन्तु यह कि उसे एक से अधिक अर्हता भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

परीक्षा	अर्हता भत्ता प्रतिमास
बीमा गम्यानों का परिमेष या चार्टर्ड बीमा संस्थान	
(i) लाइसेंसिएट	25 रुपये
(ii) एमोसिएटशिप पूरी करने पर	50 रुपये
(iii) फैलोशिप पूरी करने पर बीमाकक संस्थान	75 रुपये
(iv) कोई तीन विषय	40 रुपये
(v) कोई सात विषय	60 रुपये
(vi) फैलोशिप पूरी करने पर	75 रुपये
चार्टर्ड एकाउंट संस्थान या लागत आर सक्षम लेखाकार संस्थान	
(vii) इन्टरमीडिएट पूरा करने पर	50 रुपये
(viii) एमोसिएटशिप या फैलोशिप पूरी करने पर	75 रुपये

तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिए जाने में संबंधित कर्मचारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जहां किसी कर्मचारी को उस परीक्षाओं में से किसी परीक्षा में अर्हता करने के लिए पहले ही कोई अभियम वेतन बढ़ि या कोई अन्य आकर्षी आर्थिक फायदा दिया गया है, वहां पहले से प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करने हुए, अर्हता भत्ते की रकम में यथाचित रूप से कमी कर दी जाएगी या वह अनुज्ञेय नहीं होगा।

VI. मकान किराया भत्ता

(1) कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से, किन्तु अधिक से अधिक 200 रुपये प्रतिमास के अधीन रहते हुए, सदैव होगा। जहां किसी कर्मचारी को निगम या किसी कम्पनी द्वारा आवास सुविधा स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध कराया गया है वहां उसे कोई मकान किराया भत्ता सदैव नहीं होगा।

(2) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें आवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया गया है किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे, किन्तु वे ऐसी आवास सुविधा के लिए निगम/कम्पनी को ऐसी उपयुक्त अनु-अप्लि फीस का संदाय करेंगे जो निगम का बोर्ड समय-समय पर विनिश्चय करे।

परन्तु यह कि कोई ऐसा कर्मचारी, जिसे 1 अप्रैल, 1983 से पहले आवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया गया है, या जहां किसी कर्मचारी ने पैरा 'क' के अधीन संशोधन स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले विकल्प का प्रयोग किया है वहां वह 1 अप्रैल, 1983 के पूर्ववर्ती तारीख या संशोधन स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख को, उसे सदन मकान किराया भत्ता नब तक प्राप्त करेगा जहां तक वह निगम/कम्पनी द्वारा आवंटित आवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टरों का अधिसोप रखा रहता है।

VII नगर प्रतिकर भत्ता— पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ कर्मचारियों का मदेय नगर प्रतिकर भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा—

नौतानी का स्थान	दर	न्यूनतम रुपये	अधि- कतम रुपये
(क) 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर और पणजी तथा मांगलूर का गहरी समूह	पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्म- चारियुद्ध मूल वेतन का 10 प्रतिशत	65	140
	अधीनस्थ कर्मचारियुद्ध मूल वेतन का 8 प्रतिशत	40	60
(ख) 5 लाख और उससे अधिक किन्तु 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर,	पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्म- चारियुद्ध मूल वेतन का 6 प्रतिशत	15	90
12 लाख से अधिक जनसंख्या वाली राज्य की राजधानियाँ और चंडी- गढ़, पाण्डिचेरी तथा श्रीलंका	अधीनस्थ कर्मचारियुद्ध मूल वेतन का 1-1/2 प्रतिशत	30	35

टिप्पणी—इस पैरा के प्रयोजन के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(2) उप पैरा (i) में किसी बात के होते हुए भी, पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ कास्टर का ऐसा कोई कर्मचारी, जिस पदस्थिति वेतनमान में नियत की जा रही है, यदि पहले नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में 20 रुपये प्रतिमास की रकम मिलती रही है और जो इस स्कीम के अधीन नगर प्रतिकर भत्ते का पात्र नहीं है, उसने रकम तब तक प्राप्त करना रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर नौतान है।

VIII. पर्वतीय स्थान भत्ता—(1) पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ कास्टर में के किसी कर्मचारी का मदेय पर्वतीय स्थान भत्ता के मापमान निम्नलिखित रूप में होंगे—

- (i) जो औसत समूह तक से 1500 मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर माँटर तथा उससे अधिक की से किन्तु न्यूनतम 35 रुपये ऊँचाई पर स्थित स्थानों पर और अधिकतम 100 रुपये प्रति मास नौतान है के अधीन रहते हुए।
- (ii) जो औसत समूह तल से 1000 मीटर और उससे अधिक से किन्तु 1500 मीटर से कम की और अधिकतम 75 रुपये प्रति-मास के अधीन रहते हुए।
- मरकरा पर तथा ऐसे स्थानों पर जिनके केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप में पर्वतीय स्थान घोषित किया है नौतान है।

IX. किट भत्ता इस अनुसूची की मद (viii) में सूचीबद्ध किसी पर्वतीय स्थान का स्थानान्तरित कर्मचारियों का 400 रुपये का किट भत्ता दिया जाएगा। किट भत्ता एक पर्वतीय स्थान में दूसरे पर्वतीय स्थान को स्थानान्तरित होने पर या पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उसे किसी भी समय वापस ले लिए जाने पर, मदेय नहीं होगा।

[फा स 102/7/बीसा-IV/185]

ए के पांडेया, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1985

INSURANCE

S.O. 769(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme 1974, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1983.

(3) It shall apply to all employees—

- who are whole time employees in supervisory, clerical and subordinate staff cadre of the Corporation or of the Company on the date of commencement of this Scheme; and
- who are appointed as such by the Corporation or the Company after the date of commencement of this Scheme;

but shall not apply to persons—

- who have been promoted as Class I Officers or converted as Development Staff on or after the 1st day of April, 1983;
- who are employed under specific contracts of employment; or
- who hold part-time employment; or
- whose resignation had been accepted or whose services had been terminated before the date of publication of this Scheme in the Official Gazette.

2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as the "said Scheme"), in paragraph 3—

- after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

'(ba) 'Corporation' means the General Insurance Corporation of India formed under Section 9 of the Act'

(ii) For clauses (fa) and (fb), the following clauses shall be substituted, namely :—

(fa) "Revised terms" means the revised scales of pay and allowances as specified in the Fourth Schedule;

(fb) "Revised scales of pay" means the revised scales of pay specified in the Fourth Schedule.

3. In paragraph 4 of the said Scheme, for sub-paragraphs (4) and (5), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely :—

"(4) With effect from the date of commencement of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 1985 (hereinafter referred to as the "Amendment Scheme"), the pay and allowances of every employee shall be in accordance with the 'revised terms' and the basic salary of every employee in service as on that date shall be fixed in the revised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6A.

(5) Every employee whose basic salary is fixed in the revised scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6A, shall be paid, for the period commencing on and from the 1st day of April, 1983 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of basic salary, personal pay, if any, dearness allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the provident fund) between the "revised terms" and the "new scales of pay" (hereinafter referred to as the "existing terms") applicable to him immediately before the date of commencement of the Amendment Scheme, provided that :—

(i) an employee, who had retired from service after the 1st day of April, 1983 shall be paid the difference in amount as aforesaid for the period upto the date of his retirement alongwith the difference in amount of gratuity, if any, arising out of the Amendment Scheme, and

(ii) in the case of an employee who had died whilst in service after the 1st day of April, 1983, the difference in amount as aforesaid for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was to be paid and the difference in amount of gratuity, if any, arising out of the Amendment Scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was to be paid.

Provided further that in respect of an employee who is promoted from Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre to the cadre of officer or converted as Development Staff on or after the 1st day of April, 1983 the difference in the amount referred to above (excluding the difference in gratuity amount) upto the date of his promotion as officer or

conversion as Development Staff, shall be paid, on the basis of notional fixation of his basic salary in the revised terms.

EXPLANATION :

"For the purpose of sub-paragraph (5) the expression "Other Allowances" means house rent allowance, City Compensatory allowance, functional allowance, hill station allowance and allowance for technical qualifications as admissible to an employee."

4. For paragraph 6A of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"6A Fixation of basic salary in the revised scales of pay :—

(1) The basic salary of every employee in service as on the 31st day of March, 1983, shall be fixed at a corresponding stage in the relevant revised scale of pay with effect from the 1st day of April, 1983 ;

Provided that where an annual increment is due to such an employee on the 1st day of April, 1983, he shall be granted such an increment in the revised scale of pay immediately after such fixation of basic salary.

Provided further that that where the basic salary of such an employee is fixed at the maximum of the relevant revised scale of pay no such increment shall be granted.

(2) The basic salary of every employee appointed on or after the 1st day of April, 1983 but before the publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the relevant revised scale of pay with effect from the date of his appointment",—

Provided that the benefit on the fixation of basic salary (namely, the increase in the total of basic salary and dearness allowance under the 'revised terms' over the total of the basic salary, personal pay, if any, dearness allowance and personal allowance under the "existing terms") shall not be less than the amount specified in Column (2) of the Table annexed hereto in relation to the categories of employees specified in the corresponding entry in Column (1) of the said table :

TABLE

Category of employees	Minimum benefit per month
(1)	(2)
	Rs
Subordinate Staff	35.00
Record Clerk	40.00
All employees in the scale of pay of Assistant	50.00
Senior/Assistant/Stenographer	60.00
Superintendent	

Provided further that if the fixation of basic salary in the relevant revised scale of pay does not result in the minimum benefit as specified in the aforesaid Table, the basic salary of the employee will be fixed at one or more higher stages in the relevant revised scale of pay so as to ensure that he gets the minimum benefit specified in the aforesaid Table.

Provided also that where the fixation of basic salary at the maximum of the relevant revised scale of pay, does not enable the employee to get the minimum benefit specified in the aforesaid Table, he will be granted 'adjustment allowance' to the extent of the shortfall which allowance shall be adjusted against any future increase in basic salary or dearness allowance due on or after the publication of the Amendment Scheme in the official Gazette.

3. (a) Notwithstanding anything contained in subparagraphs (1) and (2), the employee may choose that his basic salary may be fixed in the revised scales of pay with effect from the date of publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette, in which case he shall intimate this fact in writing to the Corporation or Company within 30 days of such publication of the Amendment Scheme or such further period as may be allowed by the Managing Director or Chairman-cum-Managing Director of the Company.

(b) Where the employee opts for the fixation of his basic salary with effect from the date of such publication of the Amendment Scheme, such fixation in the revised terms shall be effected in the same manner as above including the aforesaid minimum benefit but on the basis of his aggregate emoluments (i.e. basic salary, personal pay, if any, dearness allowance and personal allowance) under the "existing terms" on the date immediately prior to the date of such publication of the Amendment Scheme :

Provided that any review of the employee's emoluments under the existing terms, even on a notional basis, shall not be effected, and no arrears for the period prior to the date of such publication of the Amendment Scheme shall be payable to him.

Provided further that where total of the aggregate emoluments (i.e. basic salary, personal pay, if any, dearness allowance and personal allowance) of any such employee in the supervisory and clerical cadres under the existing terms on the date immediately preceding the date of such publication of the Amendment Scheme and the aforesaid minimum benefit, exceeds his aggregate emoluments (i.e. basic salary, dearness allowance and adjustment allowance, if any) under the revised terms, such employee's aggregate emoluments shall be protected by grant of personal allowance to

the extent of the difference between Rs. 3,500 and the aggregate of basic salary, dearness allowance and adjustment allowance, if any, under the revised terms, and balance, if any, by grant of protection allowance :

Provided also that whilst personal allowance shall be adjusted against future increases in basic salary or dearness allowance due to the employee on or after such publication of the Amendment Scheme, the protection allowance shall continue to be unabsorbed till the date of employee's promotion to the officer's grade and on promotion of the employee as an Officer, the personal allowance, if any, shall first be absorbed to the extent possible in his aggregate emoluments on such promotion and when the full personal allowance is absorbed, the protection allowance shall be absorbed to the extent possible in the employee's aggregate emoluments on promotion as an officer :

Provided also that where the personal allowance or as the case may be, protection allowance is not fully absorbed even on promotion as an officer, the unabsorbed balance will continue as such even after the promotion :

Provided also that such personal allowance, or as the case may be, protection allowance that may continue after such promotion shall be absorbed against future increases in emoluments, as may be decided by the Chairman of the Corporation :

Provided also that the basic salary of no employee shall be fixed at basic salary higher than the maximum of the relevant revised scale of pay :

Provided also that where, as a result of the fixation of basic salary in the relevant revised scale of pay, the basic salary of an employee at two or more consecutive stages in the relevant scale of pay under the existing terms secures fixation at the same stage in the relevant revised scale of pay, the Chairman of the Corporation may provide appropriate relief by granting an additional increment earlier than the date of his normal grade increment, to the employee who is at the higher stage in the scale of pay under the "existing terms".

5. For paragraph 7 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"7 Increments—(1) increments to an employee in the grade applicable to him with effect from the date of publication of the Amendment Scheme in the official Gazette shall be due every year on the first day of the month in which the last increment was drawn or on the 1st day of the month in which he completes twelve months of continuous service.

EXPLANATION : For the purposes of this sub-paragraph "twelve months of continuous service" means a period of duty equal to twelve months excluding periods of extraordinary leave.

- (2) In respect of an employee (other than a Superintendent) whose basic salary is fixed at maximum of the revised scale of pay on the 1st day of April 1983 or on the date of publication of the Amendment Scheme under Paragraph 6A and in respect of an employee who will be reaching the maximum of the revised scale of pay at any time thereafter during the period of his service, the Managing Director or the Chairman-cum-Managing Director of the Company, as the case may be, subject to the record of work of the employee being found satisfactory, consider granting of one increment to such employee in the scale of pay of Assistant, Driver or, as the case may be, other Subordinate Staff, for every two years of service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the restrictive revised scale of pay, at the rate of last increment drawn in the scale, and not more than three such increments shall be granted :

Provided that for an employee in the scale of Senior Assistant, Stenographer or Record Clerk, one such increment in the relevant revised scale of pay may be granted for every three years of service rendered by the employee after the date of his reaching the maximum of the respective revised scale of pay, and not more than two such increments shall be granted under this sub-paragraph".

6. In paragraph 8 of the said Scheme, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

- "(4) Subject to the maximum weekly hours of work stipulated in sub-paragraphs (1) and (2), the Board of the Corporation may determine, from time to time, the number of working days in a week and the number of daily working hours."

7. In paragraph 10 of the said Scheme :—

- (1) in sub-paragraph (3), for the existing clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) Where an employee has earned leave to his credit but has not availed of the same as on the date of retirement, he may be paid cash equivalent of leave salary in respect of the period of earned leave to his credit as on the date of retirement subject to the following maximum limits, namely :—

- (i) 180 days, if the normal retirement age of the employee is 58 years; and

- (ii) 120 days, if the normal retirement age of the employee is 60 years;

Provided that earned leave standing to his credit as on the date of his death may be allowed to be encashed :

Provided further that this clause shall not apply to an employee who has been compulsorily retired, removed or dismissed in accordance with the General Insurance (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1975.

NOTE 1. "For determining the amount due to an employee for purposes of encashment of earned leave—

- (a) In the event of retirement, the leave salary shall be equal to his salary for such leave standing to his credit calculated at the rate at which he drew salary immediately preceding the date of his retirement but excluding City Compensatory Allowance, House Rent Allowance and Functional Allowance.
- (b) In the event of death of an employee, his gross total monthly emoluments (basic salary plus all allowances excluding functional allowance and officiating allowance) as on the date of death shall be taken into consideration".

NOTE 2. The amount due to an employee as a result of the encashment of earned leave remaining to his account on the date of his death shall be paid to the person to whom the concerned employee's provident fund arrears are payable.

NOTE 3. The cash equivalent of leave salary shall be paid in one lump sum as a one time settlement.

NOTE 4. The authority to grant cash equivalent of leave salary shall be an officer competent to grant leave to the employee concerned.

- (2) for the existing proviso to sub-paragraph (5), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that if an employee is suffering from any of the eight major diseases of Cancer, Leprosy, T.B., Paralysis, Brain Tumor, Cardiac Ailment, Kidney disease or mental disease, he may be allowed Special Sick Leave on half pay for a period not exceeding six months, if he has to his credit no sick leave admissible to him".

8. For paragraph 13 of the "said Scheme", the following paragraph shall be substituted, namely :—

"13 Gratuity.—(1) An employee shall be paid Gratuity in accordance with the provisions of the payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) :

Provided that gratuity payable under the Amendment Scheme shall be no case exceed

20 months' wages subject to the condition that—

- (i) where the wages last drawn by any employee exceed Rs. 1600, it shall be deemed to be Rs. 1600, for the purpose of determining the quantum of gratuity; and
- (ii) the rate at which gratuity shall be paid shall stand increased as under :—

Number of completed years of service	Rate of gratuity for each year of service in number of months' wages
12	0.6
13	0.7
14	0.8
15 or more	1.0

EXPLANATION :—In this paragraph, "wages" shall have the meaning assigned to it in clause(s) of section 2 of the payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), an employee who has rendered continuous service of not less than 15 years shall be paid gratuity which shall be higher of the two amounts calculated in accordance with sub-clause (i) and sub-clause (ii) below :—
 - (i) Gratuity calculated in accordance with sub-paragraph (1);
 - (ii) Gratuity at the rate of one month's terminal basic salary for each completed year of continuous service in respect of the first fifteen years and at the rate of half a month's terminal basis salary for each year of further continuous service subject to the condition that the total gratuity so admissible does not exceed a maximum of 20 months' terminal basis salary of Rs. 36,000 whichever is less."

9. In paragraph 19 of the said scheme, in sub-paragraph (2), the following shall be inserted at the end, namely :—

"including the introduction of Microprocessors at the various offices as may be necessary for timely generation and speedy processing of data for management information and for effective control."

10. Paragraph 20 of the said scheme shall be omitted.

11. For paragraph 24 of the said Scheme, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"24. Other benefits.—No employee shall be entitled to any benefit not arising out of this Scheme or any Scheme which may be framed by the Corporation or Company."

12. In the Third Schedule of the said Scheme :—

- (i) In clause (a), for the figures "15" the figure "7" shall be substituted;
- (ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—
"The Corporation or the Company shall reimburse to the employee, the cost of travel upto 1208 kms. each way."
- (iii) in clause (e),—(a) for the figures "1000", the figures "1208" shall be substituted; (b) for the words "sub-paragraph" the words "clause" shall be substituted;
- (iv) In clause (f), for the words and figures "more than 15 days", the words and figure "not less than 7 days" shall be substituted.

14. In the said Scheme, for the Fourth Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE FOURTH SCHEDULE

[See Paragraph 3 (fa) & (fb)]

I. Revised Scales of pay (Basic Salary)

A—Supervisory and Clerical Staff—

- (1) Superintendent : (Run off cadre)*
Rs. 1060-75-2035-80-2435.
- (2) Senior Assistant :
Rs. 715-60-1135-75-2035.
- (3) Stenographer :
Rs. 715-60-1135-75-2035.
- (4) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist and other equivalent position :
Rs. 520-30-670-45-850-60-1210-75-1660.
- (5) Record Clerk :
Rs. 490-20-730-35-905-45-1130.

B—Subordinate Staff—

- (1) Driver :
Rs. 490-20-750-25-800-30-980.
- (2) Other Subordinate Staff :
Rs. 430-10-450-20-790.

*No fresh appointment to the post of Superintendent shall be made by the Corporation or Company.

II. Functional Allowance

Employees engaged in any of the following functions as their regular and main function shall be paid a functional allowance as indicated below :

- (1) Subordinate staff working as Liftmen, Machine Operators, Head Peons, Jamadars or Daftaries
Rs. 35/- p.m.

- (2) Subordinate Staff carrying cash to or from Bank where the amount of cash carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000 or more Rs. 25/- p.m.
- (3) Cashier handling cash in an office where the total amount of cash transactions during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000; or more Rs. 75/- p.m.
- (4) Telex Operators, Punch Card Operators and Unit Record Machine Operators Rs. 40/- p.m.
- (5) Comptists Rs. 40/- p.m.
- (6) Stenographer to Chairman of the Corporation, Managing Directors, Chairman-cum-Managing Directors, General Managers, Assistant General Managers and equivalent positions Rs. 50/- p.m.
- (7) Audit Assistants Rs. 200/- p.m.

NOTE 1. The number and names of persons eligible to draw the functional allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director depending upon the load of work and administrative requirements.

NOTE 2. An employee shall draw only one functional allowance at any one time.

NOTE 3. An employee proceeding on leave shall be paid the functional allowance during his leave period other than periods of extra ordinary leave, provided that he resumes work in the same position on the expiry of his leave.

NOTE 4. No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the functional allowance attaching to that position.

NOTE 5. No employee shall refuse to work in a position carrying a functional allowance or make it a condition that he be paid such allowance where, because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.

III. Dearness Allowance

(1) The scale of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under :—

Index: All India Average Consumers Price Index Number for Industrial workers.

Base Year : 1960-100

Revision of Dearness Allowance:—Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

Rate of dearness allowance:—For every 4 points of the quarterly average over 332 points, the dearness allowance shall be calculated at the following rates :—

- (i) Basic salary of Rs. 790/- or less 1.2 of basic salary
- (ii) Basic salary of above Rs. 790/- 1% of basic salary with a minimum of Rs. 9.48 paise and maximum of Rs. 15.80 paise

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumers Price Index above 332 points in the sequence 332-336-340-344 and so on; and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figures if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the sequence. For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September, or December. The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(3) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average index for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

(4) For removal of doubt, it is clarified that the dearness allowance payable on the 1st April, 1983, shall be the amount determined in accordance with the rate specified herein on 160 point above 332 and all quarterly revisions thereafter shall be deemed to fall due on the first of the month in which the quarterly average index figures were available. Accordingly, for April, 1983, the dearness allowance payable shall be as indicated in the first entry in the Table given below and such allowance shall be deemed to have been revised thereafter in accordance with successive entries in the table.

TABLE

Dearness Allowance payable for the months	Quarterly Average Index in multiples of four points	Index points above 332 for which D.A. is payable	Rate*	
			Basic Salary upto Rs. 790	Basic salary above Rs. 790
April, 1983	492	160	48 %	40 %
May, 83 to July, 83	496	164	49.2 %	41 %
Aug. 83 to Oct. 83	520	188	56.4 %	47 %
Nov. 83 to Jan. 84	548	216	64.8 %	54 %
Feb. 84 to April, 84	556	224	67.2 %	56 %
May, 84 to July, 84	560	228	68.4 %	57 %
Aug. 84 to Oct. 84	564	232	69.6 %	58 %
Nov. 84 to Jan. 85	584	252	75.6 %	63 %
Feb. 85 to April, 85	588	256	76.8 %	64 %
May, 85 to July, 85	584	252	75.6 %	63 %
Aug. 85 to Oct. 85	600	268	80.4 %	67 %

*Subject to minimum and maximum amounts as indicated in sub-entry (ii) of entry (1) under the heading.

IV. Maximum Limit of Pay :

No employee—

- (i) Working in the Supervisory or Clerical Staff of the Corporation, or as the case may be, a company, shall at any time, draw as basic salary, special pay, if any, Dearness Allowance and Personal Allowance, an amount exceeding Rs. 3500 per month in the aggregate;
- (ii) working in the Subordinate Staff of the Corporation or as the case may be, a Company, shall at any time, draw as basic salary, special pay, if any, Dearness Allowance and Personal Allowance, an amount exceeding Rs. 2100 per month in the aggregate.

V. Allowance for Technical qualifications :

A confirmed employee who qualifies or has qualified in an examination mentioned below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination, the allowance for technical qualifications mentioned below :—

Provided that not more than one qualification allowance shall be permissible to him.

Examination	Qualification allowance per month
Federation of Insurance Institutes or Chartered Insurance Institute	
(i) Licentiate	Rs. 25
(ii) Completion of Associateship	50
(iii) Completion of Fellowship	75
Institute of Actuaries	
(iv) Any three subjects	40
(v) Any seven subjects	60
(vi) Completion of Fellowship	75
Institute of Chartered Accountants or Institute of Costs and Works Accountants:	
(vii) Completion of Intermediate	50
(viii) Completion of Associateship or Fellowship.	75

The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the employee concerned.

Where an employee has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

VI. House Rent Allowance :—

(1) The House Rent Allowance to the employee shall be payable at the rate of 10 per cent of basic salary subject to a maximum of Rs. 200 per month.

Where an employee has been provided with residential accommodation|Staff quarters by the Corporation or a Company, no House Rent Allowance shall be payable to him.

(2) Employees who are allotted residential accommodation|staff quarters shall not be entitled to any house rent allowance, but they shall pay to the Corporation|Company, for such accommodation, the appropriate licence fee as may be decided by the Board of the Corporation from time to time. Provided that an employee who has been allotted residential accommodation|staff quarters before the 1st day of April, 1983, or where an employee has exercised an option under paragraph 6A, before the date of publication of the Amendment Scheme in the Official Gazette, shall continue to receive the house rent allowance paid to him as on the date preceding the 1st day of April, 1983 or the date of such publication of the Amendment Scheme so long as he continues to occupy the residential accommodation|staff quarters allotted by the Corporation|Company.

VII. City Compensatory Allowance

(1) The scale of city compensatory allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be under

Place of posting	Rate	Minimum Rs.	Maximum Rs.
(a) Cities with population exceeding 12 lacs and Urban Agglomeration of Panaji & Marmugao	Supervisory & Clerical staff: 10% of basic salary Sub-Staffs 8% of basic salary	65	140
(b) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, state capitals with population not exceeding 12 lacs and Chandigarh, Pondicherry & Port Blair.	Supervisory & Clerical Staff: 6% of basic salary Sub-Staff: 4-1/2% of basic salary	40 45 30	60 90 36

NOTE:—For the purpose of this paragraph, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), any employee in Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre, in receipt of an amount of Rs. 20 per month as city compensatory allowance immediately before the date of fixation in the revised scale of pay and not becoming eligible for city compensatory allowance under this Scheme, shall continue to receive the said amount so long as he is posted at the same place.

VIII. Hill Station Allowance—(1) The scales of hill station allowance payable to employees in Super-

visory, Clerical and Subordinate Staff cadre shall be as follows:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) Posted at Place situated at height of 1500 metres and over, above mean sea level. | At the rate of 0% of the basic salary, subject to a minimum of Rs. 35 and a maximum of Rs. 100 per month. |
| (ii) Posted at places situated at a height of 1000 meters and over, but less than 1500 Metres, above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically | at the rate of 8% of basic salary, subject to a minimum of Rs. 30 per month and a maximum of Rs. 75 per month. |

declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.

IX. Kit Allowance :

Employees transferred to any of the hill stations listed in item VIII of this Schedule shall be paid a kit allowance of Rs. 400. The kit allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another or if the same drawn at any time during the preceding three years."

[F. No. 102/7/Ins-IV/85]

A. K. PANDYA, Addl. Secy.